वॉल्यूम 32, सं. 2, अक्टूबर, 2023

इंफोर्मेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने पुनर्विकसित वेबसाइट का शुभारंभ किया और क्रॉनिकल वन ईयर इन ऑफिस की ई-बुक जारी की

एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की पुनर्विकसित वेबसाइटों को लॉन्च करके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के महानिदेशक और राष्ट्रपति भवन और एनआईसी के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च समारोह, भारत के सर्वोच्च कार्यालय के डिजिटल विकास में एक उल्लेखनीय कदम का प्रतीक है।

एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन की पुनर्विकसित वेबसाइटों को लॉन्च करके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के महानिदेशक और राष्ट्रपति भवन और एनआईसी के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च समारोह, भारत के सर्वोच्च कार्यालय के डिजिटल विकास में एक उल्लेखनीय कदम का प्रतीक है।

एक समारोह में पुनर्निर्मित वेबसाइटों, www.Presidentofindia.gov.in और www.rashtrapatibhavan.gov.in का अनावरण किया गया, जिसने अपनी डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाने और जनता के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए राष्ट्रपति भवन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने नागरिकों को राष्ट्रपति की गतिविधियों और पहलों से संबंधित जानकारी, सेवाओं और अपडेट तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए कार्यालय के डिजिटल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, "इस डिजिटल युग में, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए एक गतिशील ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है जो अधिक पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा देता है। ये वेबसाइटें राष्ट्रपति भवन के कार्यों और राष्ट्र के प्रति योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेंगी।"

पुनर्विकसित वेबसाइटों में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर नेविगेशन और व्यापक सामग्री शामिल है जिसमें ऐतिहासिक जानकारी, भाषण, प्रेस विज्ञप्ति और राष्ट्रपति की गतिविधियों पर अपडेट शामिल हैं। वेबसाइटें मोबाइल-रेस्पॉन्सिव होने के लिए भी डिज़ाइन की गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिक विभिन्न उपकरणों पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय राष्ट्रपति के सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में एक ई-बुक के विमोचन के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के लिए पुनर्विकसित वेबसाइटों का शुभारंभ कर रही हैं।

इसके अलावा, माननीय राष्ट्रपति ने "ए ईयर इन रिव्यू: रिफ्लेक्शंस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन" शीर्षक से एक ई-पुस्तक जारी की। यह संकलन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनकी विभिन्न पहलों, प्रतिबद्धताओं और बातचीत की झलकियों का एक संग्रह प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रपति के दृष्टिकोण और स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण सहित विभिन्न सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सार दर्शाता है.

ये लॉन्च राष्ट्रपति भवन के डिजिटल परिवर्तन, पहुंच, संचार और पारदर्शिता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्षण हैं। माननीय राष्ट्रपति नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रपति भवन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

- सूचना विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय राष्ट्रपति ने पौधों की विविधता के पंजीकरण के लिए PARV समर्पित किया

12 सितंबर, 2023 को, 'किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी' के दौरान, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने PARV (पौधों की किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल) का अनावरण किया। इस उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक भाग, 'पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' के लिए एनआईसी दिल्ली के कृषि सूचना विज्ञान प्रभाग द्वारा सावधानीपूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया था।

PARV का शुभारंभ खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA), एफएओ, रोम द्वारा आयोजित और कृषि एवं किसान कल्याण, भारत सरकार मंत्रालय द्वारा आयोजित 'किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी' के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। यह कार्यक्रम 12 सितंबर, 2023 को आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर, एनएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई।

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी, इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री मनोज आहूजा, सचिव डीओए&एफडब्लू , श्री टी महापात्रा, अध्यक्ष पीपीवीएफआरए ,श्री केंट ननाडोजी, एमओए&एफडब्लू सचिव आइटीपीआरएफए रोम, डॉ. एच. पाठक, सचिव डीएआरइ एवं महानिदेशक, आईसीएआर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

PARV, https://app.plataauthority.gov.in पर उपलब्ध एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जिसे नई पौधों की किस्मों को पंजीकृत करने के लिए आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए तैयार किया गया है। यह किसानों, पारंपरिक समुदायों, सार्वजनिक और निजी बीज उद्योग के खिलाड़ियों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), सीएसआईआर, एमओईएफ के संस्थानों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी के दौरान PARV (पौधों की किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल) का अनावरण किया।

है। यह अनुलग्नकों और तस्वीरों का समर्थन करने की अनुमति देता है और कागजी कार्रवाई को कम करते हुए विभाग के वर्कफ़्लो के साथ सहजता से एकीकृत होता है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल ऑनलाइन प्रमाणपत्र निर्माण, प्लांट वैरायटी जर्नल का स्वचालित निर्माण, निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड, एमआईएस रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन स्थिति ट्रैकिंग और ईमेल और एसएमएस के माध्यम से अलर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

PARV कृषि और पौधों की सुरक्षा की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप, पौधों की किस्मों के पंजीकरण को सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा में योगदान करते हुए हितधारकों के लिए सुविधा और दक्षता लाता है।

- शैलेंद्र सक्सेना, एनआईसी-मुख्यालय

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने डेटा संचालित शासन के लिए सीएम दर्पण डैशबोर्ड लॉन्च किया

शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने 'सीएम दर्पण डैशबोर्ड' का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक के साथ-साथ राज्य और एनआईसी के अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। एनआईसी द्वारा संचालित यह अभिनव पहल, सरकारी डेटा एकत्र करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। "सीएम दर्पण डैशबोर्ड' को जटिल सरकारी डेटा को आकर्षक दृश्यों में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे नीति निर्माताओं और जनता दोनों के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाता है।

सीएम दर्पण का मतलब है "कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि के लिए मुख्यमंत्री का डिजिटल विश्लेषणात्मक और सुधार कार्यक्रम।" यह एक व्यापक डेटा एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है जो विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के डेटा का एकीकृत दृश्य प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म विशाल और जटिल डेटासेट को उपयोगकर्ता के अनुकूल विज़ुअलाइज़ेशन में परिवर्तित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है, जिसे एक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल डैशबोर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

सीएम दर्पण डैशबोर्ड कई ठोस लाभ लाता है। यह नीति निर्माताओं को वास्तविक समय, डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करके, अधिक सूचित विकल्पों को सक्षम करके निर्णय लेने, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करता है। यह नागरिकों को सरकार के प्रदर्शन के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करके उन्हें शामिल करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, वास्तविक समय की निगरानी और पूर्वानुमानित विश्लेषण के लिए धन्यवाद, यह संभावित मुद्दों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है।

'सीएम दर्पण डैशबोर्ड' का लॉन्च उत्तर प्रदेश सरकार की अपने नागरिकों के कल्याण के

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, महंत योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्रियों, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में सीएम दर्पण डैशबोर्ड का शुभारंभ करते हुए।

लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां डेटा निर्णय लेने, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी के केंद्र में है।

जैसे-जैसे इस नवोन्मेषी मंच को अपनाया जाता है और राज्य के शासन ढांचे में एकीकृत किया जाता है, इसकी क्षमताओं के विकसित और विस्तारित होने की उम्मीद है। 'सीएम दर्पण डैशबोर्ड' भारत के अन्य राज्यों और यहां तक कि अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है जो डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने शासन को बढ़ाना चाहते हैं।

- वंदना सिंह, उत्तर प्रदेश

माननीय केंद्रीय मंत्री ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम-किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया

22 जून, 2023 को नई दिल्ली में, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित पीएम-किसान मोबाइल ऐप लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। यह ऐप महत्वाकांक्षी "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" योजना का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में किसानों को आवश्यक आय सहायता प्रदान करना है। जो बात इस ऐप को अलग करती है, वह इसमें अत्याधुनिक फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का समावेश है, जो किसानों को अपने घर बैठे ही, ओटीपी या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता के बिना, दूर से ही अपना ई-केवाईसी पूरा करने की अनुमति देता है।

पीएम-किसान योजना विश्व स्तर पर सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहलों में से एक है। इस योजना के तहत, किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन किस्तों में जमा की जाती है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। यहां तक कि कोविड-19 लॉकडाउन के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी, पीएम-किसान किसानों के लिए एक मजबूत साथी साबित हुआ।

नया लॉन्च किया गया पीएम-किसान मोबाइल ऐप एक उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण है, जो Google Play Store पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध है। आय सहायता से परे, ऐप किसानों के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो योजना और उनके पीएम-किसान खातों से संबंधित आवश्यक विवरण प्रदान करता है। एक उल्लेखनीय मॉड्यूल "अपनी स्थिति जानें" सुविधा है, जो किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड तक पहुंचने, अपने बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने की स्थिति की जांच करने और उनके ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करने की अनुमति देता है।

लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने पीएम-किसान योजना की क्रांतिकारी

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप राष्ट्र को समर्पित किया

प्रकृति पर प्रकाश डाला। यह बिचौलियों को समाप्त करता है, जिससे केंद्र सरकार को प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अभूतपूर्व पैमाने पर किसानों को सीधे लाभ प्रदान करने की अनुमति मिलती है। उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, इस योजना का सफल कार्यान्वयन एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

लॉन्च कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव, श्री मनोज आहूजा और किसान कल्याण प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, एनआईसी पीएम किसान टीम के साथ एनआईसी एचओजी और डीडीजी श्रीमती प्रतिभा लोखंडे, एचओडी और डीडीजी श्रीमती माला मित्तल, के साथ प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति देखी गई।

- दीक्षा शुक्ला, एनआईसी-मुख्यालय

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में एडुटेक को बढ़ावा देने के लिए शाला दर्पण-शिक्षक ऐप लॉन्च किया

राजस्थान में 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान एनआईसी राजस्थान द्वारा विकसित दो उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री डॉ बुलाकी दास कल्ला, माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, श्रीमती जाहिदा खान, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, श्री राजेंद्र यादव, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री, डॉ. सुभाष गर्ग, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, श्री जितेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षक सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

शाला दर्पण-शिक्षक ऐप एक अभूतपूर्व उपकरण है जिसे पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह शिक्षकों को आसानी से दैनिक छात्र उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है और जब वे स्कूल परिसर में मौजूद होते हैं तो उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करने में भी सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, ऐप कर्मचारियों की छुट्टी के आवेदनों की सुविधा भी देता है। डॉ. कल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि शाला दर्पण राज्य में स्कूल प्रबंधन के लिए एक अनिवार्य उपकरण बनकर उभरा है।

वर्तमान में, यह राजस्थान के सभी 70,000+ सरकारी स्कूलों में 83 लाख से अधिक छात्रों, 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और स्कूल से संबंधित विभिन्न कार्यों, जैसे परीक्षा परिणाम, नियुक्तियाँ, पोस्टिंग, प्रवेश पंजीकरण और बहुत कुछ का समर्थन करता है। यह ऐप शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जिससे छात्रों की उपस्थिति की निगरानी करना और नियमित स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करना आसान हो जाता है। विशेष रूप से, ऐप ऑफ़लाइन कार्य कर सकता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुविधाजनक है।

शाला सम्बलन 2.0 ऐप का उद्देश्य स्कूलों को बहुमूल्य समर्थन और फीडबैक प्रदान करके राजस्थान में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। यह दौरा करने वाले अधिकारियों को उनके द्वारा

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में शिक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री, राज्य के अधिकारियों और शिक्षकों की उपस्थिति में शाला दर्पण-शिक्षक ऐप लॉन्च किया।

देखे जाने वाले किसी भी स्कूल से फीडबैक रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, जिससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जरूरतों की पहचान की जा सकती है। ऐप निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के इनपुट के आधार पर टिकट बनाता है, जिसे आवश्यक कार्रवाई के बाद बंद किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने पर मोबाइल ऐप निर्बाध रूप से ऑफ़लाइन काम करता है और इंटरनेट उपलब्ध होने पर डेटा को समन्वयित करता है।

शाला सम्बलन 2.0 ऐप की मुख्य विशेषताओं में अधिकारियों के लिए अपने निर्धारित स्कूलों के अलावा स्वेच्छा से स्कूलों का चयन करने का विकल्प शामिल है। इससे अधिकारियों को अपने प्रयासों को उन स्कूलों पर केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।

- अमित अग्रवाल, राजस्थान

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ने संपत्ति लेनदेन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 'दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग' सेवा का अनावरण किया

एनआईसी पंजाब द्वारा सर्विसप्लस फ्रेमवर्क के तहत विकसित "दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग" एप्लिकेशन, पंजाब, भारत में अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए संपत्ति लेनदेन में एक अभूतपूर्व प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा 24 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया यह एप्लिकेशन राज्य में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

लॉन्च कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री ब्रह्म शंकर शर्मा, पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा, पंजाब के वित्तीय आयुक्त श्री केपी सिन्हा और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ उपमहानिदेशक एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी पंजाब, श्री विवेक वर्मा सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से इस एप्लिकेशन के महत्व को रेखांकित किया गया। इन उपस्थित लोगों ने एनआरआई के लिए संपत्ति लेनदेन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में इस सेवा की परिवर्तनकारी क्षमता देखी।

"दस्तावेजों की एम्बॉसिंग" एप्लिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य एनआरआई को भारत में अधिकृत व्यक्तियों को उनकी ओर से संपत्ति की बिक्री निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाना है। जो बात इस एप्लिकेशन को अलग करती है, वह इसका निर्बाध स्वचालन है, जो निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए डीसी कार्यालय, मंडलायुक्त और एफसीआर (राज्य) कार्यालय सहित 29 स्थानों पर संबंधित अधिकारियों को प्राधिकरण आवेदन तेजी से जमा करने में सक्षम बनाता है।

एक उल्लेखनीय विशेषता सभी 29 साइटों के लिए समर्पित स्लॉट बुकिंग के साथ अपने पसंदीदा स्थान पर दस्तावेज़ जांच के लिए विज़िट शेड्यूल करने की उपयोगकर्ता की क्षमता है। एक उल्लेखनीय विशेषता सभी 29 साइटों के लिए समर्पित स्लॉट बुकिंग के साथ अपने पसंदीदा स्थान पर दस्तावेज़ जांच के लिए विज़िट शेड्यूल करने की उपयोगकर्ता की क्षमता है।

पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री , श्री भगवंत मान ने राज्य में संपत्ति लेनदेन में क्रांतिकारी बदलाव लाने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए 'दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग' सेवा का अनावरण किया।

यह लचीलापन अंतिम दस्तावेज़ की एम्बॉसिंग तक लागू है। पंजाब के आईएफएमएस के साथ एकीकरण से भुगतान को सुव्यवस्थित करता है, राजस्व विभाग के खाते में सीधे शुल्क जमा करने में सक्षम बनाता है, तीसरे पक्ष के कदमों को खत्म करता है, सुलह प्रयासों को कम करता है और वित्तीय दक्षता बढ़ाता है।

"दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग" सेवा की सफलता एसआईओ पंजाब के मार्गदर्शन के साथ श्री अमोलक एस. कलसी और श्री पंकज जैन के नेतृत्व में समर्पित सहयोग का परिणाम है।"दस्तावेज़ों की एम्बॉसिंग" सेवा की सफलता एसआईओ पंजाब के मार्गदर्शन के साथ श्री अमोलक एस. कलसी और श्री पंकज जैन के नेतृत्व में समर्पित सहयोग का परिणाम है।

- परमिंदर कौर, पंजाब

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने ऑटो अपील प्रणाली के माध्यम से पहुंच का विस्तार करते हुए 107 नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू कीं

डिजिटल प्रशासन और बढ़ी हुई सार्वजनिक सेवा पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव ने हाल ही में ऑटो अपील सिस्टम पर 107 नई ऑनलाइन सेवाओं की ऑनबोर्डिंग का उद्घाटन किया है। यह विकास एनआईसी के सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं की कुल संख्या को आश्चर्यजनक रूप से 210 तक लाता है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का एक सुविधाजनक और कुशल तरीका प्रदान होता है।

यह उद्घाटन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण के आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस विस्तार के साथ, पूरे केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों को अब अपनी उंगलियों पर सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त हो गई है, जिससे शासन अधिक नागरिक केंद्रित और सुलभ हो गया है।

सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत ऑटो अपील सिस्टम, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सुविधा प्रदान करने में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरा है। यह नागरिकों को एकल, उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल के माध्यम से सेवाओं तक पहुंचने और आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल हो जाती है। यह प्रणाली न केवल नागरिकों के लिए बहुमूल्य समय और प्रयास बचाती है बल्कि सरकारी कार्यालयों में भौतिक यात्राओं की आवश्यकता को भी कम करती है, जो मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

प्लेटफ़ॉर्म में जोड़ी गई 107 नई सेवाओं में विविध प्रकार के क्षेत्र और विभाग शामिल हैं। आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुँचने तक, ये ऑनलाइन पेशकशें दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं। कुछ उल्लेखनीय सेवाओं में शामिल हैं:

इस डिजिटल पहल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी पहुंच है। नागरिक अपने घरों से आराम

मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर यूटी ने जम्मू-कश्मीर के ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ी गई 107 ऑनलाइन सेवाओं की ऑनबोर्डिंग शुरू की

से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे लंबी कतारों में खड़े होने या सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बस एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, और नागरिक आधिकारिक पोर्टल (https://eunnat.jk.gov.in) के माध्यम से इन सेवाओं तक 24/7 पहुंच सकते हैं।

इन अतिरिक्त ऑनलाइन सेवाओं के जुड़ने से न केवल व्यापार करने में आसानी बढ़ती है बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा मिलता है। यह डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और नागरिकों को परेशानी मुक्त तरीके से सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। यह पहल नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में डिजिटल शासन की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाते हुए अन्य क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम करती है।

- मो. सलीम खान, जम्मू एवं कश्मीर

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news